NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK JAGRAN, Delhi, 4.7.2025
Page No. 17, Size:(4.46)cms X (3.44)cms.

मानवाधिकार आयोग ने देश की सभी कैथ लैब का आडिट का दिया निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को देश की सभी कैथ लैब का आडिट कराने का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश के दमोह के मिशन अस्पताल में फर्जी कार्डियोलाजिस्ट नरेंद्र यादव उर्फ डा. एन. जान कैम के गलत आपरेशन से सात मरीजों की मौत के मामले में जांच के बाद आयोग ने ये निर्देश जारी किए हैं। मप्र में लैब में कार्यरत सभी डाक्टरों की योग्यता की जांच को कहा गया है।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK JAGRAN, Rastriya Sanskaran, 4.7.2025
Page No. 6, Size:(2.92)cms X (8.31)cms.

देश की सभी कैथ लैब का आडिट कराए सरकार, एनसीएचआर का निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनसीएचआर) ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को देश की सभी कैथ लैब का आडिट कराने का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के मिशन अस्पताल में फर्जी कार्डियोलाजिस्ट नरेंद्र यादव उर्फ डा. एन. जान कैम के गलत आपरेशन से सात मरीजों की मौत के मामले में जांच के बाद आयोग ने ये निर्देश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश में कैथ लैब में काम करने वाले सभी डाक्टरों की योग्यता की जांच करने के लिए भी कहा गया है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने पाया है कि दमोह के मिशन अस्पताल में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन में भी अनियमितता की गई है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही तत्कालीन सीएमएचओ डा. मुकेश जैन की प्रशासनिक जांच के भी आदेश दिए हैं।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

AMAR UJALA, Delhi, 4.7.2025
Page No. 2, Size:(13.22)cms X (12.29)cms.

अचानक दिल का दौरा अनसुलझी कहानी शोध में नहीं मिला कोरोना वैक्सीन का लिंक

एम्स के विभाग कर रहे शोध, गहन परीक्षण के साथ जुटाई जा रही मृतक की हिस्ट्री

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। अचानक दिल के दौरे से मौत अनसुलझी कहानी बनी हुई है। एम्स के विभाग इसका कारण का पता लगाने के लिए शोध कर रहे हैं। बृहस्पतिवार को एम्स के विशेषज्ञ इस मामले में चर्चा करने के लिए जुटे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अचानक दिल के दौरे के मामले बढ़ने के लिए कोरोना वैक्सीन का संबंध पता लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई लिंक नहीं मिला।

कोरोना महामारी के पांच साल पहले और साल 2020 के बाद चल रहे पोस्टमार्टमों की संख्या में कोई अंतर नहीं मिला है। शोध में एम्स ने दिल के दौरे से दम तोड़ने वाले करीब 230 लोगों के शवों की जांच की। इस दौरान कोरोना वैक्सीन मृत्यु का कारण नहीं मिला। जांच के दौरान शवों में दिल, मस्तिष्क, फेफड़े सहित अन्य अंग भी सामान्य मिले। इस शोध में 25 फीसदी अटॉप्सी जांच की रिपोर्ट निगेटिव आई।

इनकी मौत का पता नहीं चला। अब इनमें मॉलिक्यूलर एनालिसिस किया जा रहा है। इसकी जीनोम स्टडी के बाद कुछ स्पष्ट हो पाएगा।

बृहस्पतिवार को अचानक दिल के दौरे से मौत के मामले में चर्चा करते हुए एम्स के प्रोफेसर। अमर उजाला

वैक्सीन ने घटाया जोखिम : डॉ. नारंग

एम्स में कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. राजीव नारंग के अनुसार, शोध बताते हैं कि जिन्होंने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाई उनमें अचानक दिल के दौरे की आंशका कम हुई। युवाओं में अचानक दिल के दौरे के पीछे रिदम की समस्या दिखी। इसमें दिल सामान्य रहता है, दिल को चलाने वाली प्रक्रिया प्रभावित होती है। ऐसे में दिल की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। युवाओं में यह कारण सामान्य है। बुजुर्ग में दूसरे कारण हैं। कोरोना के बाद लोग स्वास्थ्य के तरफ ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का चलन भी तेजी से बढ़ा है। यही कारण है कि कोई भी घटना तेजी से वायरल हो रही है।

ये हैं तीन बड़े कारण

डॉ. नारंग ने बताया कि अचानक दिल के दौरे के तीन बड़े कारण होते हैं। पहला, मॉलिक्यूलर के काम करने के तरीके में बदलाव आता है, जो बढ़ा कारण बनता है। दूसरा, दिल की मांसपेशियां मोटी हो जाती हैं और तीसरा कारण सामान्य दिल का दौरा है। सामान्य दिल के दौरे को आठ बदलाव कर रोका जा सकता है। इसमें धूम्रपान, मधुमेह, उच्च रक्तचाप व उच्च ब्लड कोलेस्ट्रॉल स्तर को काबू करना है, जबकि चार अन्य में मानसिक तनाव, मोटापा, नियमित व्यायाम और मौसमी फल-सब्जी लेना शामिल है। यह सभी जीवन शैली से जुड़ा है। यदि लोग इस तरफ ध्यान दें तो दिल के दौरे को कम कर सकते हैं।

एम्स के पैथेलॉजी विभाग के डॉ. सुधीर अरावा ने बताया कि अचानक दिल के दौरे से कोरोना के पहले और अब हो रही मौतों का आंकड़ा नहीं बदला। ऐसे में वैक्सीन का असर नहीं मान सकते।

यदि वैक्सीन का असर होता तो संख्या काफी अधिक होती। कोरोना से दम तोड़ने वालों की जांच में लंग्स ज्यादा प्रभावित दिखे। वहीं, अचानक मृत्यु की जानकारी हासिल करने के लिए एक साल के सर्वे में करीब 300 लोगों को शामिल किया गया। इसमें दो तिहाई में मौत की वजह कोरोनरी आर्टरी डिसीज मिली। कुछ के दिल में संक्रमण मिला।

इधर, एम्स में फॉरेंसिक विभाग के डॉ. अभिषेक यादव का कहना है कि 2023 में शुरू हुए इस शोध में अभी तक 300 में से 230 शव की जांच हो गई हैं। यह जांच 18 से 45 साल और 45 से 60 साल के दो ग्रुप में की जा रही है। इसमें परिवार से मृतक की हिस्ट्री, शव की गहन जांच के बाद जीनोम स्टडी की गई।

प्राथमिक रिपोर्ट में दो तिहाई मौत की वजह कोरोनरी आर्टरी डिसीज पाई गई, जो सीधे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। इसमें यह भी पाया गया कि जिन लोगों की मौत की वजह कोरोनरी आर्टरी डिसीज थी, उनमें 50 फीसदी धूम्रपान करते थे।

वैक्सीन ने 14 हजार लोगों को बचाया

एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ. संजय राय ने बताया कि कोरोना के समय दुनियाभर में प्रति 10 लाख पर करीब 15 हजार लोग दम तोड़ रहे थे। कोरोना वैक्सीन के बाद करीब 14 हजार लोगों को बचाने में सफलता मिली। यह बड़ा आंकड़ा है। महामारी के समय वैक्सीन ही एक विकल्प था। ऐसे में कुछ लोगों को जोखिम जरूर रहता है, लेकिन हमें ज्यादा लोगों को बचाना था। वहीं, भारत सरकार ने शोध के आधार पर बच्चों को वैक्सीन देने से मना कर दिया था। बच्चों में कोरोना से मौत का आंकड़ा काफी कम था।

सामान्य लोगों में भी हो सकती है थक्के जमने की समस्या

एम्स के रुधिर विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉ. तूलिका सेट ने कहा कि सामान्य लोगों में भी कई कारणों से खून के थक्के जमने की समस्या हो सकती है। काफी लोगों में उन वैक्सीन से भी खून के थक्के पाए गए जो जिन्हें वर्षों से दिया जा रहा है। यह व्यक्ति के शरीर की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। कोई भी वैक्सीन शरीर में प्रतिक्रिया करती है। यह हर व्यक्ति के शरीर के आधार पर अलग होता है।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

PIONEER, Bhubaneswar, 4.7.2025
Page No. 2, Size:(38.15)cms X (10.95)cms.

Atrocity against Dalits by cow vigilantes must be condemned

SOCIAL CANVAS

MANAS JENA

Two Dalit farmers, Baluli Naik and Bulu Naik of Singipur village under Dharakote block of Ganjam district were brutally assaulted in public, part of their heads shaved and they were compelled to eat grass and waste water. Besides, they were asked to kneel down and were also paraded on the street with all indignity and humiliation.

The perpetrators were an extortion gang, and the self-declared cow protection vigilante group. Both the victims belong to the Scheduled Caste of Hindu faith, low caste untouchables of the area. They are no way related to cow sale, slaughter or beef eating.

The Constitution of India (Art 48) explains the need for prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle to promote agriculture and animal husbandry. The matter being a State subject, Odisha has enacted the Odisha Prevention of Cow Slaughter Act, 1960. The violation of the act is a cognizable offence and attracts penalty provisions including imprisonment and fine. This has to be strictly enforced by the police but not by any religious fanatic groups or self-declared cow protection groups which will lead to unnecessary social conflict and violence defeating the very purpose of cow protection. Added to this, India has also enacted the Prevention of Cruelty against Animals Act 1960 which explains animals as all living beings other than humans.

Savarkar argued that taking cow protection to an extreme at the cost of human interest is lethal as proved in history. He further said let the cow protection be better achieved without spreading superstition; rather let it be based on economic and scientific principles like the Americans. The cow protection movement has been identified with Hindu faith and largely supported by our national leaders of a Hindu majoritarian nation, such as Dayananda Saraswati, Gandhi, Binova Bhabe, Tilak, Lajpat Rai, Madan Mohan Malviya, Rajendra Prasad and Jayaprakash Narayan. There are States having laws against cow slaughter, its business and sale of beef but many other States in India have no such law to subscribe to the argument. All the major religions in India, such as Hindu, Buddhist, Jain and Sikh have disallowed the cow slaughter which is not a case with Abrahamic religions such as Judaism, Christianity and Islam.

However, as a matter of compassion and human solidarity to the victims in Ganjam and to mount pressure on the administration to ensure justice, various social and political organisations and concerned citizens of the State have visited the area and registered their protest. The inhuman incident is a potential threat to our human values enshrined under the Constitution.

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo-motu cognizance of the atrocity case and issued a notice to the Chief Secretary of Odisha over the matter. The victims belong to weaker sections of our society, those who need special care and protection as a matter of concern for human rights violation. It is reported by many fact-finding teams that there are wounds in different parts of their bodies and specially their eyes and head injuries are a matter of concern which has not been taken seriously during the post incident treatment under police supervision. As a result, they are still suffering with serious complications that need urgent medical attention. The FIR has not been properly covering a number of offences and written hurriedly because after the incident both the victims were not in a sound mind and they were also illiterate on legal matters.

So, we suggest that all offences and provisions may be added to the FIR. Such as the people and organisations, the self-declared cow protection group, the extortionist gang and all those who were behind such violence. As both the victims belong to SC, all the provisions of PCR Act and POA Act 1989, amendment 2015, must be implemented in matters of relief, treatment, compensation and rehabilitation to help the victims return to a normal life. Adequate compensation may also be given to them as a matter of special case.

It is a fact that the socioeconomic condition of the victims' families is miserable and even their whole community has been suffering all indignity because of their low caste identity. They are in a panic condition without protection. It is the duty of the police to stop caste-based atrocities occurring in the areas and create legal awareness on human rights involving all sections of people to build social harmony.

Along with this particular case, there are also reports of other such incidents of crimes occurring in different parts of the State such as Malkangiri and Nabarangpur districts particularly against vulnerable sections such as SCs, STs, religious minorities and women which is also equally alarming. They are facing social alienation and insecurity has been growing among them while their life, liberty and dignity are under continuous threat in the absence of adequate socio-legal protection. It is a question to the credibility of our law-and-order system though our Constitution has guaranteed a number of special provisions to protect the weaker sections from social discrimination and many forms of exploitation.

(manasbbsr15@gmail.com)

PIONEER, Bhubaneswar, 4.7.2025
Page No. 1, Size:(17.59)cms X (18.10)cms.

Girl gives birth during exam: NHRC seeks report

PNS ■ Jajpur

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Jajpur Superintendent of Police (SP) in connection with a Class-X Dalit student giving birth during her HSC Examinations in February 2025.

The 15-year-old girl developed severe abdominal pain while appearing for the examination on February 26 and subsequently, gave birth to a daughter at the Bari Government Hospital. She had completed two papers but missed her mathematics examination scheduled for the following day.

Following a petition by human rights activist and Orissa High Court advocate Akhand, the NHRC has demanded an action taken report within four weeks.

The petition highlighted gross negligence by school authorities, Anganwadi staffs and local administration for failing to detect the pregnancy.

Police investigation revealed that the student's 25-year-old neighbour had repeatedly sexually assaulted her when her parents were away at work. Later, the accused was arrested and charged under Section 376 2(n) of the IPC and Section 8 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.

The petitioner has demanded strict action against the guilty, rehabilitation for the victim and implementation of preventive measures in schools to avoid such incidents in the future.

2 panels to probe Shimla bldg collapse, 4-lane highway work

Drones To Help Identify Areas At Risk Due To Slope Cutting

Times News Network

Shimla: Deputy commissioner (Shimla) Anupam Kashyap Thursday formed two committees under additional DMs to probe the reasons for the collapse of a five-storey building in Bhattakufer on June 30, and also to report on the ongoing construction of a four-lane highway from Kaithlighat to Dhalli.

Chairing a meeting here, Kashyap ordered a committee under additional DM (law and order), Pankaj Sharma, to submit a detailed report on the causes of the collapse of the Bhattakufer building, the damages, and assistance for the affected. It will also report if nearby houses are at risk due to the four-lane highway construction.

Another committee has been constituted under additional DM (protocol), Jyoti Rana, to submit a report on the ongoing four-lane construction work from Kaithlighat to Dhalli. Representatives from PWD, NHAI, police, the construction company, and other stakeholders are members of the committee. It will oversee if the construction company is adhering to rules or not. The 27km four-lane work falls under the jurisdiction of Shimla.

The committee will also provide information on vulnerable areas created by the construction work in its report. The deputy commissioner asked NHAI to submit a report within two days, detailing when the consultant flagged dangers posed by the four-lane construction.

The report must include what steps were taken by the company at such sites following the consultant's report. The NHAI will also report on land acquisition for the highway.

PTI

The multi-storey building that collapsed following heavy rainfall at Bhattakufer in Shimla on June 30

'Attack' on NHAI official: BJP neta seeks NHRC role

Shimla: Amid the rift between NHAI and panchayati raj minister Anirudh Singh, BJP leader and former MP Avinash Rai Khanna has written to NHRC seeking its intervention by terming the minister's alleged attack on an NHAI official as a "clear-cut human rights violation." Forwarding a letter by NHAI Engineers' Association's chief Narendra Singh to NHRC chairman Thursday, Khanna said his letter is self-explanatory about the "brutal assault" on NHAI manager (technical) Achal Jindal in the Bhattakufer area of Shimla on June 30.

The panchayati raj minister claimed Wednesday that an FIR was registered against him just to cover up the building collapse incident in Bhattakufer due to NHAI's negligence in highway construction. TNN

ORISSA POST, Bhubaneswar, 4.7.2025
Page No. 5, Size:(7.40)cms X (9.37)cms.

NHRC seeks ATR on minor girl's childbirth during board exam

PNN & AGENCIES

Jajpur, July 3: The National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognizance of a bizarre incident in Jajpur district, where a Class X minor girl gave birth to a baby while appearing for the board examinations.

Acting on a petition filed by human rights activist and Orissa High Court lawyer Akhand, the NHRC has issued a notice to the Superintendent of Police, Jajpur, seeking an action taken report (ATR) within four weeks.

The incident took place February 26, 2025, when the minor girl, a student of Panchayat High School, Rampur under Bari block, developed severe abdominal pain and gave birth to a baby girl at Bari Government Hospital.

She had appeared for two papers of the High School Certificate Examination and was scheduled to write her Mathematics paper February 27, 2025, but her condition prevented her from continuing.

The petitioner alleged gross negligence by school authorities, Anganwadi staff, and the local administration for failing to notice the pregnancy, which also indicates a possible case of sexual abuse, constituting a violation under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act. He further demanded action against those responsible, rehabilitation for the victim, and preventive measures in schools.

Taking the matter seriously, the NHRC has sought a detailed report from the Jajpur SP within four weeks.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

STATESMAN, Bhubaneswar, 4.7.2025

Page No. 3, Size:(2.55)cms X (14.50)cms.

Minor girl's childbirth: NHRC issues notice to Odisha police

National Human Rights Commission

STATESMAN NEWS SERVICE

BHUBANESWAR, 3 JULY:

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognizance of a bizarre incident in Jajpur district, where a Class 10 minor girl gave birth to a baby while appearing for the 10th Standard Board examinations.

Acting on a petition filed by human rights activist Mr. Akhand, the NHRC has issued a notice to the Superintendent of Police, Jajpur, seeking an Action Taken Report within four weeks.

The incident took place on 26 February when the minor girl, a student of Panchayat High School, Rampur under Bari block, developed severe abdominal pain and gave birth to a baby girl at Bari Government Hospital. She had appeared for two papers of the High School Certificate Examination and was scheduled to write her Mathematics paper on 27 February.

The petitioner alleged gross negligence by school authorities, Anganwadi staff, and the local administration for failing to notice the pregnancy, which also indicates a possible case of sexual abuse, constituting a violation under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act. He further demanded action against those responsible, rehabilitation for the victim, and preventive measures in schools.

The States

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK BHASKAR, Bhagalpur, 4.7.2025

Page No. 3, Size:(8.78)cms X (7.63)cms.

मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया

भागलपुर| घोघा थाना क्षेत्र की महिला ने अपने देवर के बेटे पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने एसएसपी हृदय कांत से 10 दिन में रिपोर्ट मांगी है। आरोप है कि कुछ लोग हमे डायन कहकर अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पीड़िता का कहना है कि इसकी सूचना घोघा थानेदार को दी गई तो उन्होंने कार्रवाई नहीं की। पीड़िता का यह भी आरोप है कि आरोपियों ने उनके घर के सिंक और सीवरेज लाइन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। जिससे खाना बनाने से लेकर अन्य जरूरी कार्य में भी दिक्कत हो रही है।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

NAI DUNIYA, Gwalior, 4.7.2025
Page No. 7, Size:(12.71)cms X (15.78)cms.

मानव अधिकार आयोग ने दिए देश के सभी कैथ लैब का आडिट कराने के आदेश

- फर्जी कार्डियोलाजिस्ट के हाथों सात मरीजों की मौत का मामला
- कैथ लैब के डाक्टरों की योग्यता की जांच करने को भी कहा

नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोहः राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को देश की सभी कैथ लैब का आडिट कराने का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के मिशन अस्पताल में फर्जी कार्डियोलाजिस्ट नरेंद्र यादव उर्फ डा. एन. जान कैम के गलत आपरेशन से सात मरीजों की मौत के मामले में जांच के बाद आयोग ने ये निर्देश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश में कैथ लैब में काम करने वाले सभी डाक्टरों की योग्यता की जांच करने के लिए भी कहा गया है। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक व आयकर आयुक्त और स्वास्थ्य विभाग के सचिव को इस संबंध में पत्र जारी किया गया है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने पाया है कि दमोह के मिशन अस्पताल में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन में भी अनियमितता की गई है। आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही तत्कालीन सीएमएचओ डा. मुकेश जैन की प्रशासनिक जांच के भी आदेश दिए हैं।

विदेशी फंडिंग की भी हो जांच

आयोग के सदस्यों ने जांच के दौरान मिशन अस्पताल से डा. अजय लाल का जुड़ाव होने और धोखाधड़ी, कदाचार, फंड की हेराफेरी आदि में भी संलिप्तता पाई है। आयोग ने डा. अजय लाल के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, चिकित्सा लापरवाही, कदाचार, फंड की हेराफेरी आदि से संबंधित आरोपों पर प्रासंगिक आपराधिक प्रविधानों के तहत एफआइआर दर्ज करने के निर्देश डीजीपी को दिए हैं। आयोग के संज्ञान में यह भी आया है कि डा. अजय लाल अस्पताल चलाने के लिए कथित अवैध विदेशी फंडिंग प्राप्त करने में शामिल हैं। इसकी जांच के भी निर्देश दिए गए हैं।

मिशन की 1.30 एकड़ जमीन है शासकीय

आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मिशन अस्पताल जहां बना है, वह नजूल भूमि घोषित है। यहां के अनधिकृत निर्माण को ढहाने के निर्देश थे। भूखंड क्रमांक 86/1 जिसे 86/2, 1.30 एकड़ को अवैध घोषित किया गया था। आयोग ने माना कि संबंधित नजूल अधिकारी व नगरपालिका परिषद के अधिकारी कलेक्टर के आदेशों का पालन करने में विफल रहे। आयोग ने इस मामले में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश शासन को दिए हैं। पूरे मामले और इससे जुड़े सभी तथ्यों की पुलिस जांच की आवश्यकता भी बताई है।

मानव अधिकार आयोग ने दिए देश के सभी कैथ लैब का आडिट कराने के आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को देश के सभी कैथ लैब का आडिट कराने का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के मिशन अस्पताल में फर्जी कार्डियोलाजिस्ट नरेंद्र यादव उर्फ डा. एन. जान कैम के गलत आपरेशन से सात मरीजों की मौत के मामले में जांच के बाद आयोग ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश में कैथ लैब में काम करने वाले सभी डाक्टरों की योग्यता की भी जांच करने के लिए भी कहा गया है। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक व आयकर आयुक्त और स्वास्थ्य विभाग के सचिव को इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने पाया है कि दमोह के मिशन अस्पताल में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन में भी अनियमितता की गई है। आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं। तत्कालीन सीएमएचओ डा. मुकेश जैन की प्रशासनिक जांच के भी आदेश दिए हैं।

- फर्जी कार्डियोलाजिस्ट के हाथों सात मरीजों की मौत का मामला
- कैथ लैब के डाक्टरों की योग्यता की जांच करने को भी कहा

विदेशी फंडिंग की भी हो जांच

आयोग के सदस्यों ने जांच के दौरान मिशन अस्पताल से डा. अजय लाल का जुड़ाव होने और धोखाधड़ी, फंड की हेराफेरी आदि में भी संलिप्तता पाई है। आयोग ने डा. अजय लाल के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, चिकित्सा लापरवाही, कदाचार, फंड की हेराफेरी आदि से संबंधित आरोपों पर प्रासंगिक आपराधिक प्रविधानों के तहत एफआइआर दर्ज करने के निर्देश डीजीपी को दिए हैं।

मिशन की 1.30 एकड़ जमीन है शासकीय

आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मिशन अस्पताल जहां बना है, वह नजूल भूमि घोषित है।

यहां के अनधिकृत निर्माण को ढहाने के निर्देश थे। भूखंड क्रमांक 86/1 जिसे 86/2, 1.30 एकड़ को अवैध घोषित किया गया था। आयोग ने माना कि संबंधित नजूल अधिकारी व नगरपालिका परिषद के अधिकारी कलेक्टर के आदेशों का पालन करने में विफल रहे। आयोग ने इस मामले में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश शासन को दिए हैं। पूरे मामले और इससे जुड़े सभी तथ्यों की पुलिस जांच की आवश्यकता भी बताई है।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

NAI DUNIYA, Bhopal, 4.7.2025
Page No. 8, Size:(17.09)cms X (14.87)cms.

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने देश के सभी कैथ लैब का आडिट के दिए निर्देश

दमोह के मिशन अस्पताल में फर्जी कार्डियोलाजिस्ट के गलत आपरेशन से सात की मौत का मामला

नवदुनिया प्रतिनिधि, दमोह : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को देश के सभी कैथ लैब का आडिट कराने का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के मिशन अस्पताल में फर्जी कार्डियोलाजिस्ट नरेंद्र यादव उर्फ डा. एन. जान कैम के गलत आपरेशन से सात मरीजों की मौत के मामले में जांच के बाद आयोग ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश में कैथ लैब में काम करने वाले सभी डाक्टरों की योग्यता की भी जांच करने के लिए भी कहा गया है। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक व आयकर आयुक्त और स्वास्थ्य विभाग के सचिव को इस संबंध में पत्र जारी किया गया है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने पाया है कि दमोह के मिशन अस्पताल में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन में भी अनियमितता की गई है। आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं। तत्कालीन सीएमएचओ डा. मुकेश जैन की प्रशासनिक जांच के भी आदेश दिए हैं।

दमोह का मिशन अस्पताल। फाइल फोटो

10-10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए

मिशन अस्पताल में पदस्थ डा. एन. जान कैम पर आरोप हैं कि उन्होंने फर्जी डिग्री के आधार पर दमोह के सात मरीजों की एंजियोप्लास्टी की और उनकी लापरवाही से मरीजों की जान चली गई। आयोग ने शासन को मिशन अस्पताल प्रबंधन और डा. कैम से राशि वसूलकर सात मरीजों के वैध उत्तराधिकारियों को 10-10 लाख रुपये देने के आदेश दिए हैं।

मिशन की 1.30 एकड़ जमीन है शासकीय : आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मिशन अस्पताल जहां बना है, वह नजूल भूमि घोषित है। यहां के अनधिकृत निर्माण को ढहाने के निर्देश थे। भूखंड क्रमांक 86/1 जिसे 86/2, 1.30 एकड़ को अवैध घोषित किया गया था। आयोग ने माना कि संबंधित नजूल अधिकारी व नगरपालिका परिषद के अधिकारी कलेक्टर के आदेशों का पालन करने में विफल रहे। आयोग ने इस मामले में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश शासन को दिए हैं। पूरे मामले और इससे जुड़े सभी तथ्यों की पुलिस जांच की आवश्यकता भी बताई है।

विदेशी फंडिंग की भी हो जांच: आयोग के सदस्यों ने जांच के दौरान मिशन अस्पताल से डा. अजय लाल का जुड़ाव होने और धोखाधड़ी, कदाचार, फंड की हेराफेरी आदि में भी संलिप्तता पाई है। आयोग ने डा. अजय लाल के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, चिकित्सा लापरवाही, कदाचार, फंड की हेराफेरी आदि से संबंधित आरोपों पर प्रासंगिक आपराधिक प्रविधानों के तहत एफआइआर दर्ज करने के निर्देश डीजीपी को दिए हैं।

आयोग ने यह भी पाया है कि डा. लाल आयुष्मान कार्ड वाले रोगियों के उपचार में विदेशी दान प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए इन आरोपों की विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा जांच कराए जाने के निर्देश भी डीजीपी को दिए हैं। आयोग के संज्ञान में यह भी आया है कि डा. अजय लाल पुत्र स्व. विजय लाल अस्पताल चलाने के लिए कथित अवैध विदेशी फंडिंग प्राप्त करने में शामिल हैं। फर्जी कार्डियोलाजिस्ट डा. एन. जान कैम सहित अस्पताल प्रबंधन पर गैर इरादतन हत्या, धोखाधड़ी और जालसाजी आदि से संबंधित आरोपों को लेकर प्रबंध समिति पर सात अलग-अलग एफआइआर दर्ज करने के भी निर्देश आयोग ने दिए हैं।

Times of India

3 more arrested in Ganjam torture case

https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/3-more-arrested-in-ganjam-torture-case/articleshow/122233148.cms

Jul 4, 2025, 05.03 AM IST

Berhampur: Police on Thursday arrested three more persons for their alleged involvement in the physical torture of two Dalit persons near Singipur under Dharakote police station limits in Ganjam district on June 26.

The National Human Rights Commission (NHRC) also took suo motu cognizance of the incident and sought reports from the govt in next two weeks.

"The three arrested persons include Sunil Swain (21) and Ashish Barala (19) of Bethuar and Santosh Kumar Polai (32) of Nabaratnapur," Chandrika Swain, inspector in-charge of Dharakote police station, said.

With the fresh arrests, the total number of arrests in the case has gone up to 16. Police said they were searching for others allegedly involved in the incident.

Two persons of Singipur, belonging to the Scheduled Caste, were allegedly beaten up, forced to eat grass and drink drain water on suspicion of illegally smuggling cattle by a group of people. The accused persons had also snatched their mobile phones and cash and their heads were forcibly tonsured partially. They were also forced to crawl on knees for around 2km.

The NHRC has observed that the case is a violation of human rights and issued notices to the chief secretary and the DGP on Wednesday, calling for a detailed report on the matter. The report is expected to include the action taken against the perpetrators and compensation, if any, provided to the victims.

The incident triggered widespread outrage, while opposition political parties, including BJD, Congress and the Left parties, condemned the incident and sought stringent action against the accused persons. A fact-finding team of the Congress also visited Singipur and discussed with the victims. Dalit Mahasabha, an outfit of Scheduled Caste in Ganjam unit, on Wednesday demonstrated in front of the revenue divisional commissioner (southern division) in Berhampur demanding strong action against the accused.

The Statesman

Minor gives birth while sitting at Board Exam, NHRC issues notice to Odisha Police

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognizance of a bizarre incident in Odisha's Jajpur district, where a Class 10 student, a minor, gave birth to a baby while appearing for the 10th standard Board examinations.

https://www.thestatesman.com/india/minor-gives-birth-while-sitting-at-board-exam-nhrc-issues-notice-to-odisha-police-1503452863.html

SNS | BHUBANESWAR | July 3, 2025 2:02 pm

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognizance of a bizarre incident in Odisha's Jajpur district, where a Class 10 student, a minor, gave birth to a baby while appearing for the 10th standard Board examinations.

Acting on a petition filed by human rights activist and Orissa High Court lawyer Akhand, the NHRC has issued a notice to the Superintendent of Police, Jajpur, seeking an Action Taken Report within four weeks.

The incident took place on February 26, 2025, when the minor girl, a student of Panchayat High School, Rampur under Bari block, developed severe abdominal pain and gave birth to a baby girl at Bari Government Hospital. She had appeared for two papers of the High School Certificate Examination and was scheduled to write her Mathematics paper on February 27, 2025, but her condition prevented her from continuing.

The petitioner alleged gross negligence by school authorities, Anganwadi staff, and the local administration for failing to notice the pregnancy, which also indicates a possible case of sexual abuse, constituting a violation under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act. He further demanded action against those responsible, rehabilitation for the victim, and preventive measures in schools.

Taking the matter seriously, the NHRC has sought a detailed report from the Jajpur SP within four weeks.

Times of India

Minor girl gives birth during exam: NHRC issues notice to Jajpur SP

https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/minor-girl-gives-birth-during-exam-nhrc-issues-notice-to-jajpur-sp/articleshow/122228099.cms

Jul 3, 2025, 05.13 PM IST

Kendrapada: The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to Jajpur SP in connection with a Class 10 Dalit student giving birth during her board examinations earlier this year.

The 15-year-old girl developed severe abdominal pain while appearing for her high school certificate examination on Feb 26 and subsequently, gave birth to a daughter at Bari Government Hospital. She had completed two papers but missed her mathematics examination scheduled for the following day.

Following a petition by human rights activist and Orissa high court advocate Akhand, the NHRC has demanded an action taken report within four weeks. The petition highlighted gross negligence by school authorities, Anganwadi staff and local administration for failing to detect the pregnancy.

Police investigation revealed that the student's 25-year-old neighbour had repeatedly sexually assaulted her when her parents were away at work. The accused has been arrested and charged under Section 376 2(n) of the IPC and Section 8 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.

The petitioner has demanded strict action against those responsible, rehabilitation for the victim and implementation of preventive measures in schools to avoid such incidents in the future.

OMMCOM NEWS, Online, 4.7.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Ommcommnews

NHRC Issues Notice To Jajpur SP Over Minor Girl's Childbirth During Board Exam

https://ommcomnews.com/odisha-news/nhrc-issues-notice-to-jajpur-sp-over-minor-girls-childbirth-during-board-exam/

by OMMCOM NEWS | July 3, 2025 in Odisha

Bhubaneswar: Concerned over a minor girl's childbirth during her board examination, the National Human Rights Commission (NHRC) has slapped a notice on the Jajpur Superintendent of Police.

The rights body has sought an Action Taken Report (ATR) within four weeks from the Jajpur SP, following a petition filed by human rights activist and Orissa High Court Advocate Mr. Akhand.

According to the petitioner, the minor girl gave birth to a baby while appearing for her Board examinations on February 26, 2025. The girl, a student of Panchayat High School, Rampur, complained of severe abdominal pain and rushed to Bari Government Hospital, where she delivered a child.

The petitioner alleged gross negligence by school authorities, Anganwadi staff, and the local administration for failing to notice the pregnancy, which suggests a possible case of sexual abuse under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act.

The petitioner demanded action against those responsible, rehabilitation for the victim, and preventive measures in schools.

Univarta

बोर्ड परीक्षा के दौरान छात्रा बनी मां, ओडिशा पुलिस को नोटिस जारी

https://www.univarta.com/news/other-states/story/3505801.html

राज्य » अन्य राज्य Posted at: Jul 3 2025 2:59 PM

भुवनेश्वर 03 जुलाई (वार्ता) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने ओडिशा के जाजपुर जिले में 10वीं कक्षा की एक छात्रा की बोर्ड परीक्षा के दौरान प्रसव होने के मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया है।

मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं उड़ीसा उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अखंड की ओर से दायर याचिका पर कार्रवाई करते हुए, एनएचआरसी ने जाजपुर के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

Sabguru News

बोर्ड परीक्षा के दौरान छात्रा बनी मां, ओडिशा पुलिस को NHRC का नोटिस जारी

https://www.sabguru.com/nhrc-asks-state-govt-for-report-on-lawyers-custodial-torture

द्वारा sabguru news - July 3, 2025

भुवनेश्वर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने ओडिशा के जाजपुर जिले में 10वीं कक्षा की एक छात्रा की बोर्ड परीक्षा के दौरान प्रसव होने के मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया है।

मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं उड़ीसा उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अखंड की ओर से दायर याचिका पर कार्रवाई करते हुए, एनएचआरसी ने जाजपुर के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक गत 26 फरवरी बारी ब्लॉक के अंतर्गत रामपुर पंचायत हाई स्कूल की छात्रा को परीक्षा देते समय पेट में तेज दर्द हुआ और उसने बारी सरकारी अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया। इससे पहले उसने दो विषयों की परीक्षा दे चुकी थी और दूसरे दिन उसे गणित का पेपर देना था, लेकिन स्वास्थ्यगत कारणों से वह आगे परीक्षा नहीं दे सकी।

याचिकाकर्ता ने स्कूली अधिकारियों, आंगनवाड़ी कर्मचारियों और स्थानीय प्रशासन पर छात्रा के गर्भ धारण करने के मामले में घोर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। याचिकाकर्ता का ये भी कहना था कि ये यौन उत्पीड़न का भी मामला हो सकता है जो पोस्को कानून के अंतर्गत आता है।

याचिकाकर्ता ने इस मामले में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई और पीड़ित के पुनर्वास के साथ साथ स्कूलों में एहतियाती उपाय लागू करने की मांग की। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एनएचआरसी ने जाजपुर के पुलिस अधीक्षक से चार हफ्तों के अंदर रिपोर्ट मांगी है।

Hindustan Times

Spl panel formed to probe Shimla building collapse

https://www.hindustantimes.com/cities/chandigarh-news/spl-panel-formed-to-probe-shimla-building-collapse-101751564220196.html

By Shailee Dogra, Shimla

Published on: Jul 04, 2025 05:12 AM IST

Shimla deputy commissioner (DC) Anupam Kashyap said a committee has been formed under the chairmanship of additional district magistrate (law & order) Pankaj Sharma

Days after the building collapsed in Shimla's Bhattakufer area, the district administration on Thursday ordered an inquiry into the incident.

Shimla deputy commissioner (DC) Anupam Kashyap said a committee has been formed under the chairmanship of additional district magistrate (law & order) Pankaj Sharma. "A special committee will investigate the incident of collapse of a five-storey building in Bhattakufer and will give a detailed report on the reasons for the collapse, the damage and provide assistance to the affected. Along with this, the committee will also submit a detailed report regarding the safety of adjoining houses," said DC after a meeting.

Know the latest trending news with HT. Read detailed articles here

On July 1, a five-storeyed building collapsed in Bhattakufer area of Shimla. The building owner Ranjana Verma and the residents had pinned the blame on the four-laning work by the National Highway Authority of India (NHAI). The issue snowballed into a political storm after the panchayati raj minister Anirudh Singh was booked for assaulting the NHAI officials.

A case against NHAI was registered on the complaint of building owner Ranjana on Tuesday. A case against NHAI officials, technical manager Achal Jindal and Yogesh, a site engineer, was also registered on the complaint by ward committee member of Chamiyana panchayat residents of Sanjay Van in Bhattakufer.

Another committee, constituted under the chairmanship of additional district magistrate protocol Jyoti Rana, will get the status report of the four lane construction work going on from Kaithlighat (from where the border of Shimla district starts) to Dhali, the DC said. The committee will have 12 members, including from public works department, NHAI, police, construction company and other stakeholders.

"This committee will identify the work being done by the company. Action will be taken if the rules are not being followed," said DC.

The four-lane work of about 27 km from Kaithlighat (from where the border of Shimla district starts) to Dhali comes under Shimla district.

The committee will also give information in the report about the sensitive areas formed due to the construction work.

Deputy commissioner has also instructed NHAI to submit a detailed assessment report along with steps taken within two days.

They were also asked to submit reports given by the consultant on dangers arising out of the construction of the four-lane from Kaithlighat to Dhali tunnel.

“Along with this, information will also have to be given in the report about what steps were taken by the company at such places after the consultant’s report,” said DC, while seeking report from Gawar Construction Limited, the company which is carrying out work for NHAI.

Talking about identifying other vulnerable houses, the DC said, “Drone survey is being done through the police and such places are being identified where there is a possibility of danger due to cutting. The company and NHAI have been instructed to inspect the dumping site so that there is no adverse effect on the land adjoining these sites due to monsoon.”

It may be mentioned that Panchayati Raj minister, Anirudh Singh on Wednesday had pointed out that 700 complaints are pending alone in Shimla against NHAI with regards to the danger to the properties.

The district administration said that about 20 families have been affected by the four-lane construction work.

“The families demand that the affected building owner should be provided financial assistance as well as rent bythe company. Apart from taking appropriate steps to secure the partially affected houses,” the deputy commissioner said, instructing the public works department to get the partially damaged buildings evaluated so that they can be compensated after assessing the damage and NHAI has been directed to take effective steps to save the property of the residents.

BJP MP seeks NHRC intervention

The BJP state in-charge and former Rajya Sabha MP Avinash Rai Khanna has sought intervention from the National Human Rights Commission (NHRC) following the attack on NHAI officials in Shimla allegedly by state’s panchayati raj minister Anirudh Singh.

In a letter sent on Wednesday to the NHRC, Rai termed the incident a violation of human rights and requested the human rights body to take action and direct the government in this regard. A copy of the letter was made available on Thursday by the BJP.

The Week

Assault on NHAI officials BJP's Himachal state in-charge seeks NHRC's intervention

https://www.theweek.in/wire-updates/national/2025/07/03/des41-hp-nhai-assault-nhrc.html

PTI Updated: July 03, 2025 16:52 IST

Shimla, Jul 3 (PTI) The BJP state in-charge and former Rajya Sabha MP Avinash Rai Khanna has sought intervention from the National Human Rights Commission (NHRC) following the attack on a National Highway Authority of India (NHAI) officials in Shimla allegedly by state's Panchayati Raj Minister Anirudh Singh.

In a letter sent on Wednesday to the NHRC, Rai termed the incident a violation of human rights and requested the human rights body to take action and direct the government in this regard. A copy of the letter was made available on Thursday by the BJP.

The matter pertains to an alleged assault on National Highways Authority of India (NHAI) employees, Achal Jindal, a manager of a four-lane project in Shimla, and his associate Yogesh, who reportedly were called to a room by Singh and beaten up.

The minister, at a press conference on Wednesday, denied the allegations and said that "the FIR does not mean that I am guilty."

He also claimed widespread irregularities in road construction works by the NHAI and called its officials the "most corrupt in the country."

Meanwhile, the NHAI Engineers Association, in the letter to NHRC, also demanded action against the minister and six others for their alleged assault on Jindal and said that the official had sustained serious injuries to his head.

The alleged incident occurred on Monday when the minister was inspecting a building collapse site in Bhatta Kuffar in his assembly constituency Kasumpti in the suburbs of Shimla city and called NHAI officers there.

The NHAI officials alleged that they were beaten by the minister inside the room.

On Tuesday, Singh was booked for wrongful restraint, voluntarily causing hurt, criminal force to deter a public servant while performing his duty and intentional insult after Jindal filed a police complaint.

The minister, in his defence, claimed that the NHAI officials' behaviour was "inappropriate", following which the residents lodged complaints against the officials.

The owner of the collapsed building, Ranjana Verma, has filed a complaint against the NHAI and the company engaged in the project after the building collapsed.

Two more cases were also registered against the two NHAI officials by eight residents of Bhatta Kuffar, whose houses have been affected, and a ward member of Chamiyana Panchayat for wrongful restraint, endangering life or personal safety of others, intentional hurt and criminal liability of several people.

Condemning the "heinous assault" on NHAI officials, Union Minister Nitin Gadkari on Tuesday wrote on Facebook that "I have taken serious cognisance of the matter and

spoken with Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu, urging immediate and exemplary action against all perpetrators following which the CM said that action would be taken as per the law."

(This story has not been edited by THE WEEK and is auto-generated from PTI)

PTI, Online, 4.7.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Press Trust of India

Assault on NHAI officials: BJP’s Himachal state in-charge seeks NHRC’s intervention

https://www.ptinews.com/story/national/assault-on-nhai-officials:-bjp's-himachal-state-in-charge-seeks-nhrc's-intervention/2696063

SHIMLA: (Jul 3) The BJP state in-charge and former Rajya Sabha MP Avinash Rai Khanna has sought intervention from the National Human Rights Commission (NHRC) following the attack on a National Highway Authority of India (NHAI) officials in Shimla allegedly by state's Panchayati Raj Minister Anirudh Singh.

In a letter sent on Wednesday to the NHRC, Rai termed the incident a violation of human rights and requested the human rights body to take action and direct the government in this regard. A copy of the letter was made available on Thursday by the BJP.

The matter pertains to an alleged assault on National Highways Authority of India (NHAI) employees, Achal Jindal, a manager of a four-lane project in Shimla, and his associate Yogesh, who reportedly were called to a room by Singh and beaten up.

Devdiscourse

Controversy Erupts Over Alleged Assault on NHAI Officials in Shimla

An alleged assault on NHAI officials by Himachal Pradesh Panchayati Raj Minister Anirudh Singh has sparked a request for intervention by the NHRC. The incident unfolded during a site inspection and has led to multiple police complaints, with Singh denying charges and questioning NHAI's integrity.

https://www.devdiscourse.com/article/law-order/3491531-grudge-fueled-attack-leads-to-arrests-in-delhi

Devdiscourse News Desk | Shimla | Updated: 03-07-2025 16:44 IST | Created: 03-07-2025 16:44 IST

An alleged assault by Himachal Pradesh's Panchayati Raj Minister Anirudh Singh on National Highway Authority of India (NHAI) officials in Shimla has stirred controversy, prompting BJP's Avinash Rai Khanna to request National Human Rights Commission (NHRC) intervention.

The minister allegedly called NHAI officials, including project manager Achal Jindal, to a room where they claim to have been beaten. Singh denied the allegations, highlighting irregularities in road construction works by the NHAI and labeling its officials corrupt.

Union Minister Nitin Gadkari condemned the attack and discussed the incident with Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu, urging swift action against the culprits. Multiple police complaints have been filed, deepening the conflict between political figures and NHAI representatives.

(With inputs from agencies.)

Himachal Scape

BJP flags National human rights commission over Himachal minister-NHAI officer assault matter

https://himachalscape.com/bjp-flags-national-human-rights-commission-over-himachal-minister-nhai-officer-assault-matter/

Last updated: July 3, 2025 2:19 pm

Team Himachal Scape

3 Min Read

Shimla, July 3,

Adding more spice to the ongoing rift between Himachal Pradesh's Panchayati Raj Minister Anirudh Singh and the National Highways Authority of India (NHAI), BJP leader and former MP Avinash Rai Khanna has approached the National Human Rights Commission (NHRC), seeking urgent intervention into what he has described as a "clear-cut human rights violation."

Khanna's complaint comes in the wake of an FIR filed against Minister Anirudh Singh and his alleged supporters for brutally assaulting NHAI Project Manager Achal Jindal in Shimla. The incident, which has already caused considerable stir in the administrative and political circles, is now taking a sharper political turn.

In his letter dated July 3 to the NHRC Chairman, Khanna enclosed a detailed representation from Narendra Singh, President of the NHAI Engineers Association, which narrates the alleged assault and expresses deep concern over the state's apparent inaction. The letter, while highlighting lapses by the state machinery, also makes a case for safeguarding the dignity and safety of public servants working on critical infrastructure projects.

"The above said facts are a clear-cut human rights violation due to non-action on the part of the public servant," Khanna noted, calling upon the Commission to take cognizance and fix accountability.

The BJP leader, who is also a former Rajya Sabha Chief Whip and BJP National Vice President, accused the state administration of gross negligence. He underlined that such incidents not only endanger the morale and security of government officers but also set a dangerous precedent of political interference in the functioning of national institutions.

While the complaint is framed in the language of institutional justice and human rights, its timing and framing evidently indicate a deeper political strategy. The involvement of a senior BJP leader in the matter—especially at a time when the state government is battling criticism over its infrastructure and law-and-order performance—adds a layer of political pressure on the ruling dispensation in Himachal Pradesh. Khanna's move

appears to be part of a larger political effort by the opposition to spotlight the perceived administrative failings of the state government.

The letter also urges the NHRC to direct the state government to uphold the rule of law and protect professionals like NHAI engineers from violence and political intimidation, underscoring the need for an impartial investigation and immediate redressal.

Whether the NHRC takes up the matter remains to be seen, but this episode has undoubtedly intensified the political heat in Himachal Pradesh, especially as questions mount about how the FIR against a sitting minister will proceed in a highly charged environment.

LatestLY

देश की खबरें | एनएचआईए अधिकारियों से मारपीट मामले में मानवाधिकार आयोग हस्तक्षेप करे: भाजपा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के हिमाचल प्रदेश मामलों के प्रभारी और पूर्व राज्यसभा सदस्य अविनाश राय खन्ना ने राज्य के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह द्वारा शिमला में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों के साथ कथित तौर पर की गई मारपीट मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से हस्तक्षेप की मांग की है।

https://hindi.latestly.com/agency-news/human-rights-commission-should-intervene-in-the-assault-of-nhia-officials-bjp-r-2680211.html

एजेंसी न्यूज Bhasha | Jul 03, 2025 07:16 PM IST

शिमला, तीन जुलाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के हिमाचल प्रदेश मामलों के प्रभारी और पूर्व राज्यसभा सदस्य अविनाश राय खन्ना ने राज्य के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह द्वारा शिमला में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों के साथ कथित तौर पर की गई मारपीट मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से हस्तक्षेप की मांग की है।

राय ने बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को भेजे एक पत्र में उक्त घटना को मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया और मानवाधिकार निकाय से इस संबंध में कार्रवाई करने और सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया। भाजपा की ओर से बृहस्पतिवार को पत्र की एक प्रति उपलब्ध कराई गई।

यह मामला एनएचएआई के कर्मचारियों, शिमला में चार लेन परियोजना के प्रबंधक अचल जिंदल और उनके सहयोगी योगेश पर हमले से संबंधित है। आरोप है कि उन्हें सिंह ने एक कमरे में बुलाया और उनकी पिटाई की।

मंत्री ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में आरोपों से इनकार किया और कहा कि " प्राथमिकी दर्ज होने का अभिप्राय यह नहीं है कि मैं दोषी हूं।" उन्होंने एनएचएआई द्वारा सड़क निर्माण कार्यों में व्यापक अनियमितता का भी आरोप लगाया और इसके अधिकारियों को "देश में सबसे भ्रष्ट" बताया।

इस बीच, एनएचएआई अभियंता संघ ने भी एनएचआरसी को लिखे पत्र में जिंदल पर कथित हमले के लिए मंत्री और छह अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और कहा कि अधिकारी के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं।

कथित घटना सोमवार को उस समय हुई जब मंत्री शिमला शहर के उपनगरीय क्षेत्र कसुम्पटी में अपने विधानसभा क्षेत्र के भट्टा कुफ्फार में निरीक्षण कर रहे थे जहां एक इमारत ढह गयी थी। इमारत ढहने के बाद मंत्री ने वहां एनएचएआई के अधिकारियों को बुलाया था।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

PUNJAB KESARI, Online, 4.7.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Punjab Kesari

Himachal: NHAI विवाद के बीच सीएम सुक्खू से मिले मंत्री अनिरुद्ध सिंह, अधिकारी से मारपीट के आरोप नकारे

https://m.himachal.punjabkesari.in/himachal-pradesh/news/minister-anirudh-singh-met-cm-sukhu-amid-nhai-controversy-2175722

punjabkesari.in Thursday, Jul 03, 2025 - 09:20 PM (IST)

शिमला (कुलदीप): एनएचएआई विवाद के बीच ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने वीरवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान मुख्यमंत्री को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया तथा एनएचएआई अधिकारी से मारपीट के आरोपों से इंकार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जानलेवा निर्माण कार्य को किया जा रहा है, जिसमें घटिया निर्माण कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डंगों का निर्माण कार्य भी संतोषजनक तरीके से नहीं किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदारों के साथ मजबूत नैक्सेस चल रहा है।

उल्लेखनीय है कि एनएचएआई विवाद के दौरान मुख्यमंत्री शिमला से बाहर थे, जिस कारण मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपना पक्ष रखा। अनिरुद्ध सिंह ने मुख्यमंत्री के साथ श्रम एवं रोजगार विभाग की बैठक में भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आवश्यकता महसूस होने पर खुद उस क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं, जहां पर एन.एच.ए.आई. निर्माण कार्य से घरों को नुक्सान पहुंचा है। हालांकि लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस क्षेत्र का दौरा करके एनएचएआई से बेहतर तालमेल बनाकर आगे बढ़ने की बात कही है।

अविनाश राय खन्ना ने मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को लिखा पत्र

उधर, हिमाचल प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने एनएचएआई विवाद को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखा है। उन्होंने इस मामले का संज्ञान लेकर कानून के अनुसार कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने इस विवाद में लोक सेवक यानी मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने पर आपत्ति जताई है।

वित्त विभाग से बैठक कर सकते हैं सीएम

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। इस दौरान वह मौजूदा वित्तीय हालात के बीच कर्मचारियों को डी.ए. देने के विकल्प तलाशे जाने पर चर्चा कर सकते हैं।

First India

NHRC puts J'jhunu under watch over civic lapses

https://firstindia.co.in/news/india/nhrc-puts-jjhunu-under-watch-over-civic-lapses

03 Jul-2025 10:24 AM

Written By: Pradeep Gadhwal

Jhunjhunu: During a meeting in Jhunjhunu, National Human Rights Commission (NHRC) Special Monitor Balakrishan Goel issued a strong warning to district officials, declaring that the district will now be under strict NHRC surveillance. He said complaints of potholes, water scarcity, damaged electric poles, or accident-prone areas will be treated as human rights violations and official negligence.

Goel instructed that deficiencies be addressed within a week and ordered regular water testing and weekly reporting to the Collector. He also cautioned against NGOs misusing the human rights label, directing authorities to report any such organisations exerting undue pressure.

Outlook

India's Custodial Death Toll: Ajith Kumar's Case Highlights Over 4,200 Fatalities from 2020 to 2022

The Demise Of Ajith Kumar In Tamil Nadu Has Once Again Opened the Pandora's Box on Custodial Deaths

https://www.outlookindia.com/national/indias-custodial-death-toll-ajith-kumars-case-highlights-over-4200-fatalities-from-2020-to-2022

Saher Hiba Khan

Updated on: 3 July 2025 4:55 pm

A custodial death in Tamil Nadu's Sivaganga District has sparked fresh questions about police accountability and the way custodial death cases are handled. Ajith Kumar, 27, worked as a security guard at the Madapuram Kaliamman Temple near Madurai, which is managed by the Hindu Religious & Charitable Endowments Department (HR&CE). On June 28, he was taken in for questioning by the Thirupuvanam Police based on a complaint of theft filed by a temple devotee. A video has gone viral, showing him being beaten with a lathi in a secluded spot by police personnel.

The following day, Kumar was declared dead. His family alleges that he was tortured while in police custody, and the post-mortem report recorded 18 injuries to his body. Based on the findings and the video, five policemen were arrested, and six others were suspended. The case has been transferred to the Central Bureau of Investigation (CBI) and a judicial inquiry has also been ordered.

Kumar's death is not the first time such a case has come to light. Custodial deaths have been reported from several states, and in many instances, questions are raised about how suspects are treated during interrogation. Official data from the Ministry of Home Affairs, dated March 22, 2022, shows that a total of 4,247 custodial deaths were reported in India between April 2020 and February 2022. This includes 255 deaths in police custody and 3,992 in judicial custody.

In the 2021-22 alone, 155 people died in police custody across the country—Tamil Nadu reported four deaths in police custody and 93 in judicial custody. The National Human Rights Commission (NHRC), which receives these reports, has the authority to recommend compensation and disciplinary action if any negligence or wrongdoing is found.

In Kumar's case, the police initially claimed that he had collapsed while being questioned, but the video and post-mortem report have raised doubts about the police's version.

A study released this year by the Common Cause Lokniti Programme, titled Status of Policing in India Report (SPIR) 2025: Police Torture and (Un)Accountability, has highlighted certain behaviour within the police force that may explain why these cases

keep happening. The report is based on a survey of 8,276 police personnel across 17 states and Union territories. It found that many respondents felt the use of force was part of routine police work.

Around 30 per cent of police personnel said that using third-degree methods is justified in serious cases. Nine per cent said it was acceptable even for petty offences. Some also said that slapping uncooperative witnesses or hitting family members of an accused was sometimes justified. The study found that officers, who regularly carry out interrogations, were more likely to justify such methods.

The report also looked at how legal procedures are followed during arrests. Forty-one per cent of police personnel said that procedures are always followed, whereas 24 per cent said they are rarely or never followed. Just over half of the respondents said that it is always possible to produce an arrested person before a magistrate within 24 hours. These are basic legal requirements, but the report shows that their implementation is not uniform.

According to the SPIR report, there are discrepancies in how custodial deaths are reported by official and independent sources. For instance, in 2020, the National Crime Records Bureau (NCRB) reported 76 custodial deaths; the NHRC reported 90, while the National Campaign Against Torture (NCAT), a civil society group, documented 111 deaths.

In Kumar’s case, the time between his detention and death was less than two days. According to the SPIR 2025, most police custody deaths take place in the first 24 hours of arrest. In 2022, 55 per cent of such deaths, reported by the NCRB, were of people not yet remanded to judicial custody. In Gujarat, between 2018 and 2022, 96 per cent of police custody deaths happened in the first 24 hours.

The NHRC requires a judicial inquiry in every case of custodial death. But as per SPIR 2025, in 2022, only 35 per cent of such cases led to inquiries. Between 2018 and 2022, legal cases were registered in just 10 per cent of police custody deaths. Among those, chargesheets were filed only in 12 per cent. Convictions remained at zero.

Kumar’s case shares similarities with past incidents—a person is detained; there are allegations of torture; and, then a custodial death is reported. Sometimes there is video evidence, as in this case, which adds pressure for action. But without such documentation, many cases do not reach the same level of attention. Kumar’s death is being investigated because a video was recorded. In many other cases, without such evidence, the families struggle to prove what actually happened.

Tamil Nadu has seen other custodial deaths in recent years. In 2020, the deaths of P. Jayaraj and J. Bennix in Sathankulam gained national attention. That case also involved allegations of custodial torture and was eventually transferred to the CBI. The trial in that case is ongoing.

In Kumar's case, his family has said they want the investigation to be fair. They have also said that Kumar had no criminal background. At the moment, the outcome of the CBI probe is awaited.

According to the NHRC records, compensation was recommended in 137 cases of custodial deaths in 2021-22. In Tamil Nadu, compensation was suggested in three cases, which amounted up to Rs 8 lakh. But when it comes to follow-up action beyond compensation, the numbers are lower. In 2021-22, only one case from Tamil Nadu saw a recommendation for disciplinary action. There were no prosecutions. Nationally, there were no convictions in custodial death cases during that period.

While compensation may be offered and some officers may face suspension or arrest, the data shows that long-term accountability remains limited.

HINDU, Online, 4.7.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Hindu

Six minor girls `trapped in horrific conditions' rescued from orchestra groups in Bihar

The rescued girls were trafficked from New Delhi, West Bengal, and Nepal. The operation was carried out based on intelligence provided by Narayani Seva Sansthan, and inputs from the National Human Rights Commission (NHRC)

https://www.thehindu.com/news/national/bihar/six-minor-girls-trapped-in-horrific-conditions-rescued-from-orchestra-groups-in-bihar/article69765128.ece

Published - July 03, 2025 12:40 am IST - PATNA

Amit Bhelari

Acting on inputs from the National Human Rights Commission and intelligence provided by Narayani Seva Sansthan (NSS), the Saran police on Wednesday (July 2, 2025) raided multiple orchestra groups and rescued six minor girls from horrific conditions of sexual exploitation and abuse.

Three of the rescued girls are from Bihar, and the remaining were trafficked from West Bengal, Delhi, and Nepal. The girls, the youngest of whom was found to be 15 years old, revealed that the orchestra operators not only subjected them to inhumane treatment but also forced them to dance to vulgar songs. If they refused, they were tortured and physically assaulted.

Last week, the Patna High Court, while hearing a petition filed by Just Rights for Children (JRC), issued a notice to the Bihar Government demanding immediate regulation and monitoring of orchestra groups to prevent the trafficking, sexual abuse, and exploitation of minor girls.

The raids were carried out on three groups: New Orchestra Group, Shiv Shakti Orchestra, and Muskan Orchestra and Musical Group. While the girls, aged between 15 and 17, were rescued, the orchestra owners escaped during the raids and are currently absconding.

Police efforts to trace and arrest them are underway. The rescued minor girls were taken to the Ekma police station and later presented before the Child Welfare Committee.

Orchestra hub

Saran district is known as a hub of orchestra activity in Bihar. For years, minor girls have been lured from other states and even across international borders with false promises of opportunity and income.

Once brought into these groups, the girls are trapped, exploited, and subjected to sexual abuse. They are made to wear revealing clothes and forced to perform obscene dances for male audiences.

For the past two years, Narayani Seva Sansthan, a partner of JRC, has been running a dedicated campaign against the exploitation of minor girls in orchestra groups.

Rituraj, Secretary of Narayani Seva Sansthan, appreciated the active support and cooperation of the government and administration. He said that it is only with the administration’s help that the police are now able to take strict action against traffickers and orchestra owners who illegally employ and exploit minor girls.

Luring vulnerable girls

Rituraj added, “These orchestra groups have opened offices across various states, from where their agents lure girls from poor and vulnerable families — tempting them with promises of a glamorous future. Once trapped, these girls are forced to perform obscene dances in skimpy clothing, and many are pushed into prostitution.”

In the official press statement, Saran police said, “On the instructions of Senior Superintendent of Police (SSP) Saran, Dr. Kumar Ashish, personnel from Ekma police station conducted an early morning raid today and freed 6 minor girls.

In this regard, Ekma Police Station Case No. 256/25 has been registered, and further action is being taken.

“Under the direction of SSP Saran, a total of 194 girls have been freed from immoral prostitution in Saran district, since May 2024, and 24 cases have been registered and 61 accused arrested and sent to judicial custody. Raids are continuing to arrest the remaining accused,” police said in the statement.

HINDUSTAN, Online, 4.7.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Hindustan

घोघा में बुजुर्ग महिला को प्रताड़ित करने में मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी से मांगी रिपोर्ट

महिला ने डायन कहने और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया भागलपुर, वरीय संवाददाता घोघा थाना

https://www.livehindustan.com/bihar/bhagalpur/story-woman-alleges-harassment-by-brother-in-law-s-son-in-bhagalpur-nhrc-takes-action-201751588584229.amp.html

Fri, 4 Jul 2025, 05:53:AM Newswrap हिन्दुस्तान, भागलपुर

भागलपुर, वरीय संवाददाता घोघा थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने अपने देवर के बेटे पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। उनकी शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने मामले में भागलपुर एसएसपी से 10 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। महिला का आरोप है कि आरोपी डायन कहकर प्रताड़ित करते हैं। अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पीड़िता का कहना है कि इसकी सूचना घोघा थानेदार को दी गई तो उन्होंने आरोपी का पक्ष लिया और कार्रवाई नहीं की। पीड़िता का यह भी आरोप है कि आरोपियों ने उनके घर के सिंक और सीवरेज लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया जिससे खाना बनाने और अन्य जरूरी कार्य में भी परेशानी हो रही।

शिकायतकर्ता ने आयोग से हस्तक्षेप की मांग की थी। आयोग ने माना है कि महिला के लगाए आरोप प्रथम दृष्टया मानवाधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होता है। आयोग का कहना है कि एसएसपी अगर रिपोर्ट नहीं सौंपेंगे तो आयोग लोक स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम 1993 की धारा 13 के तहत बलपूर्वक शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।